(b) whether the said amount was deducted from the salaries of their employees as contemplated under the Income Tax Act;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, what are the details of the head from which the said amount was withdrawn for deposit and what is the rationale behind?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) to (d) No tax was deposited by Bharat Petroleum Corporation Ltd., and Hindustan Petroleum Corporation Ltd., on account of shares disinvested by the Government, in favour of the employees during the year 1994-95.

Progress in the Kandla-Bhatinda Pipeline Project

4619. SHRI PRAMOD MAHAJAN:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what is the present position of the Kandla-Bhatinda Pipeline Project;

(b) what was its original estimated cost and what is its present revised cost; when the work was started and how much expenditure has so far been incurred on it;

(c) what are the reasons for the slow progress in the execution of the project; and

(d) by when it is likely to be completed and at what cost?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) to (d) Government had, on 10-8-93, approved the proposal of IOC for the Revised Cost Estimates of Kandla-Bhatinda Pipeline of Rs. 2391.84 crores (FE component of Rs. 891.30 crores) against the original cost estimates amounting to Rs. 917.55 crores (FE component of Rs. 204.54 crores) approved on 29-8-90. The revised mechanical completion schedule is 21 months from the date of Government's approval of Revised Cost Estimates.

The main work on the project started in August, 1993 and the overall physical progress by the end of March, 1995 was 61.80 per cent and the expenditure incurred was, approximately, Rs. 1169.32 crores including FE component of Rs. 444.25 crores upto March 1995.

The reasons for the slow progress in execution of the project are slow progress in Detailed Design and Engineering, delay in procurement of indigenous materials, and delay in mobilisation and slow progress of main line and station construction etc.

The entire project is expected to be mechanically completed by November, 1995 and is expected to be within the approved Revised Cost Estimates.

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

4620. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान मूल्यों के आधार पर देश में 1997 तक पैट्रोलियम उत्पादों के आयात बिल की राशि 20,000 करोड़ रु० तक हो जाने की संभावना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की मांग की वार्षिक

वृद्धि दर सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई वार्षिक वृद्धि दर से अधिक है ;

(ग) यदि नहीं, तो सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी ;

(घ) क्या सरकार द्वारा देश में बढ़ती हुई मांग का विश्लेषण करने हेतु इनमें से प्रत्येक उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर का पता लगाया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, मिट्टी का तेल और अन्य उद्योगों में प्रयुक्त पेट्रोलियम उत्पादों की वार्षिक वृद्धि दरें अलग-अलग कितनी-कितनी रही हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) आयात बिल अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों, देशी फूड उत्पादन, शोधन क्षमता के क्रियान्वित होने तथा मांग के वास्तविक रूप से क्रियान्वित होने पर निर्भर करेगा ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग की वार्षिक वृद्धि दर सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की वार्षिक वृद्धि दर से अधिक नहीं है।

(ग) से (ङ) अपेक्षित जानकारी अनुपत्र में दी गयी है। [देखिए परिशिष्ट 173, अनुपत्र संख्या 94]

कैप्टन गैस सर्विस गाजियाबाद द्वारा डी० बी० सी० जारी किया जाना

4621. **मौलाना अबदुल्ला खान आजमी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कैप्टन गैस सर्विस गाजियाबाद द्वारा जारी की गई डी बी सी का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1995 के दौरान कितने ग्राहकों को डी०बी०सी० दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार ने उन्हें रेग्यूलेटर बदले जाने पर मूल्य वसूल करने का अधिकार दिया हुआ है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) मैसर्स कैप्टन गैस सर्विस गाजियाबाद द्वारा निर्गत दूसरी सिलिंडर सुविधा (डीबीसी) निम्नानुसार है :—

वर्ष	निर्गत डीबीसी की संख्या
1993 . .	602
1994 . .	414

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के जो एलपीजी ग्राहक दूसरा सिलिंडर लेना चाहते हैं उन्हें अपना नाम संबद्ध वितरकों के पास दर्ज कराने की जरूरत होती है। कोटा उपलब्ध होने पर वितरक पहले आओ पहले पाओं के आधार पर दूसरा सिलिंडर जारी करते हैं ।

(ग) आईओसी की नीति के अनुसार गड़बड़ी वाले उन पी आर को मुफ्त बदल दिया जाता है जिनको ग्राहक छेड़ते नहीं हैं । यदि रेग्यूलेटर ग्राहक की छेड़छाड़ की वजह से खराब हो जाते हैं तो ऐसे रेग्यूलेटरों को बदलने के लिए 150 रु० की दर से प्रशुल्क वसूल किया जाता है ।

Supply of LPG to Orissa

4622. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the severe scarcity of LPG in Orissa;

(b) if so, the steps taken to enhance the allocation of LPG to that State; and